

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रामक्ष अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र० क्र० 523 दो/2011 विरुद्ध आदेश दिनांक 10-03-11
पारित अपर कलेक्टर, शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 55/निगरानी/08-09.

- 1- महिला लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. सुभाषचन्द्र
- 2- अनिलकुमार पुत्र स्व. बालकेशनदास
- 3- दिलीप सिंहल पुत्र स्व. सुभाष सिंहल
- 3- मनीषा पुत्री स्व. सुभाष चन्द्र पत्नी महेश
द्वारा कर्त्ताखानदान व मुख्तयारआम कैलाश सिंहल
समस्त नि० निजी नवग्रह मंदिर के पीछे,
कमलागंज, शिवपुरी, म०प्र०

--- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- ओमप्रकाश राठौर पुत्र स्व. भूरेराम
- 2- लक्ष्मीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
- 3- प्रमोद राठौर उर्फ राजू पुत्र ओमप्रकाश
- 4- प्रवीण राठौर पुत्र ओमप्रकाश
- 5- सुनील राठौर पुत्र ओमप्रकाश
समस्त निवासी अम्बेडकर पार्क के सामने,
कमलागंज, शिवपुरी, म०प्र०

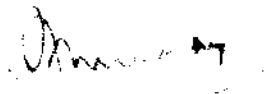
--- अनावेदकगण

श्री अनिल कुमार सिंहल आवेदकगण की ओर से
श्री एस०कं० श्रीवास्तव अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 25.03.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
(जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर



कलेक्टर, शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 55/निगरानी/08-09 में पारित आदेश दिनांक 10 03 11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण अनिलकुमार आदि ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि आवेदकगण ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराने पर पता चला कि सर्वे नं० 211 रकबा 7 बीघा 6 विस्वा के अंशभाग 67.89 वर्गमीटर पर अनावेदकगण ओमप्रकाश आदि का अवैध कब्जा है। उन्होंने अवैध कब्जा हटाकर कब्जा वापिस दिलाने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार, शिवपुरी ने अपने आदेश दिनांक 7-8-04 द्वारा आवेदनपत्र 2 वर्ष की अवधि का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्तुत किये जाने से सुनवायी योग्य नहीं होने से खारिज किया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10-03-11 द्वारा खारिज की है। अतः आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

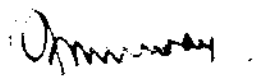
3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण ने निगरानी में यह मुद्दा उठाया गया है कि विचारण न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा मूल आवेदनपत्र का ना तो जबाब प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। अनावेदकगण द्वारा धारा 32 का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार ने निरस्त कर दिया था और इस निरस्त किये गये आवेदनपत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है। उनका तर्क है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य का तहसीलदार ने अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं करते हुए अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत फर्जी एव बनावटी फोटो कॉपी के आधार पर आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से



अनावेदकगण ने बलपूर्वक अवैध अतिक्रमण 01-03-02 को किया गया था जिसमें प्रमाण में डिप्टी कलेक्टर के.एल.राय के दिनांक 01-03-02 के पत्र की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गयी। भूमि का सीमांकन दिनांक 11-01-03 को हुआ, आवेदकगण द्वारा धारा 250 का आवेदनपत्र दिनांक 01-05-03 को प्रस्तुत किया गया जो निर्धारित समयवधि 2 वर्ष के अन्दर है। उनका यह भी तर्क है कि पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में सर्वे क0 211 आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर अनावेदक का मकान होना व खसरे में ओमप्रकाश राठौर भूमिस्वामी नहीं होना प्रतिवेदित किया है जिस पर अपर कलेक्टर द्वारा विचार नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है कि धारा 32 के आवेदन एवं सहपत्रों की प्रति आवेदकगण को उपलब्ध नहीं करायी गयी और पटवारी की रिपोर्ट भी एकपक्षीय प्राप्त की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए आवेदकगण का आवेदनपत्र खारिज किया गया है, इस कारण तहसीलदार का आदेश अपील योग्य होने से निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर पिछले 15-20 वर्षों से अनावेदकगण का मकान बना हुआ है जिसमें वे निवासरत हैं। उनका यह भी तर्क है कि निर्मित भवन की भूमि का कब्जा पाने के लिये धारा 250 के प्रावधान लागू नहीं होते और इस संबंध में उन्होंने मेरे समक्ष 1971 रा.नि. 464 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।


5/ इसके जबाब में आवेदक का कथन है कि तहसीलदार द्वारा धारा 32 के आवेदनपत्र के आधार पर पटवारी रिपोर्ट प्राप्त कर उसके आधार पर आदेश पारित किया गया है, इसलिये निगरानी ग्राह्य योग्य है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी



थी और यह आपत्ति अपर कलेक्टर के समक्ष नहीं उठायी गयी. इसलिये अपर कलेक्टर के निगरानी आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होने से निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6/ तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-8-04 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22-10-04 द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना खारिज किया गया। आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 7-8-04 एवं 22-10-04 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी। संहिता की धारा 46 (ख) के अनुसार 'पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किये गये आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती, इस कारण आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी विधिक प्रावधान के अनुसार थी। आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानी आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, इसलिये अनावेदकगण की आपत्ति व इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष मान्य योग्य नहीं है।

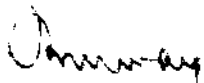
7/ तहसील न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा धारा 250 के आवेदनपत्र का जबाव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार द्वारा दिनांक 5-4-04, 21-4-04, 30-4-04, 5-5-04 को अवसर देने बाद भी अनावेदकगण द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने से तहसीलदार द्वारा दिनांक 18-5-04 को आवेदन का जबाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया। दिनांक 30-6-04 को अनावेदक अभिभाषक द्वारा आवेदक साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण करने पर तहसीलदार द्वारा अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिये। तहसीलदार ने दिनांक 22-7-04 को अनावेदक द्वारा साक्ष्य का अवसर चाहे



जाने पर अन्तिम अवसर प्रदान कर प्रकरण दिनांक 29-7-04 को नियत किया। अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और तहसीलदार ने अनावेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया। तहसीलदार ने आदेश पत्रिका दिनांक 31-7-04 में यह अंकित किया है कि

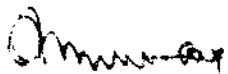
“प्रकरण पेश। प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। आवेदक की ओर से खसरा वर्ष 2004 का प्रस्तुत किया। अनावेदक अभिभाषक द्वारा कुछ लेखी साक्ष्य पेश किया। प्रकरण में तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण अध्ययन व आदेश हेतु। सी एफ 5.8.04”

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण द्वारा धारा 250 के आवेदनपत्र का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार ने उभय पक्ष के अभिभाषकों के प्रकरण में तर्क श्रवण करने के पश्चात आदेश हेतु नियत दिनांक 5-8-04 को पटवारी से पंचनामा एवं रिपोर्ट मगाने आदेश दिये। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 91-92 पर उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट एवं पंचनामा से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा दिनांक 5-8-04 को पंचनामा एवं रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष दिनांक 6-8-04 को प्रेषित की गयी है। इस मौका पंचनामों में आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उन्हें मौका निरीक्षण की सूचना दी गयी। ऐसी दशा में एकपक्षीय पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आवेदकगण का धारा 250 का आवेदनपत्र तहसीलदार द्वारा खारिज करना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के भी विपरीत है। आवेदकगण ने भूमि सर्वे क्रमांक 211 के भूमिस्वामी होने के संबंध में खसरे की छाया प्रतियों प्रस्तुत की गयी हैं। आवेदकगण द्वारा उनके स्वत्व की भूमि पर अवैध कब्जा की जानकारी सीमांकन कराने पर होना आवेदनपत्र में उल्लेख किया गया, जिसका खण्डन अनावेदकगण द्वारा नहीं किया गया और इस संबंध में तहसील में सीमांकन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है। भरत बनाम गनपत (1975 रा.नि. 159) में यह व्यवस्था दी गयी है कि एक व्यक्ति भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदारी की



भूमि दूसरे के अनाधिकृत कब्जे में दबाई गई. सीमांकन से वह भूमि वादी की होना पाई गई. सीमांकन के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर दावा बेदखली तथा वापसी कब्जा किया जा सकता है।

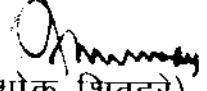
8/ अनावेदकगण द्वारा धारा 32 का आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकों का 15-20 वर्ष पुराना भवन होने से संहिता की धारा 250 के प्रावधान लागू नहीं होना एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त करने का अनुरोध किया। इस आवेदनपत्र का जबाव आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 33-34 पर है तथा जबाव के साथ विक्रयपत्र की छाया प्रति एवं अतिक्रमण भाग का वर्तमान स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया गया है। इनके अवलोकन से विदित होता है कि अनावेदक ओमप्रकाश द्वारा कय किये गये पुराने भवन की परिमाण 17 फुट X 21.5 फुट -365 है, किन्तु उसके द्वारा अतिक्रमण कर वर्तमान में निर्माण 31.5 फुट X 39.75 फुट = 1252 में किया है अर्थात् 887 वर्गफुट पर अनावेदकगण ने अतिक्रमण कर निर्माण किया है। यह निर्माण आवेदकगण ने धारा 250 के आवेदनपत्र में 01-03-02 को बलपूर्वक करना दर्शाया है और इस संबंध में शिकायत डिप्टी कलेक्टर के समक्ष करना बतलाया है। पटवारी ने अपने प्रतिवेदन एवं पंचनामा दिनांक 5-8-04 में 10 X 30 = 320 में ओमप्रकाश का भवन वर्ष 1992 में निर्मित होना बताया है। आवेदकगण द्वारा उक्त भवन के अलावा जो अतिरिक्त भूमि पर अनावेदकगण ने जबरन कब्जा कर निर्माण किया गया उसकी वापसी की माँग की थी, किन्तु तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते समय इन पर कोई ध्यान नहीं दिया है और आवेदकगण के अखण्डित दावे को समयवधि बाह्य मानकर खारिज करने में त्रुटि की है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अनावेदक को तथाकथित अनुबन्ध पत्र की छाया प्रति, जो सुभाष चन्द एवं अनिल कुमार पुत्रगण बालकिशन द्वारा ओमप्रकाश राठौर के



निगरानी क0 523-दो/2011

पक्ष में लिखा गया है, के आधार पर आवेदकगण के भूमिस्वाग्नी स्वत्व की भूमि पर कोई वैध स्वत्व प्राप्त हैं तो उन्हें इसका निराकरण सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कराना चाहिये।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 10-03-11 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 7-8-04 एवं 22-11-04 निरस्त किये जाते हैं।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0